21 सप्ताह का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को। पीड़िता के पिता ने कहा था कि यह बच्चा उसे जिंदगीभर न भुलाए जा सकने वाली घटना की याद दिलाता रहेगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 21 जुलाई 2019

चुनाव आयोग के फ्लैक्स पर निर्भया के दुष्कर्मी की तस्वीर!

विवाद ▸ सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद मामले ने पकड़ा तूल

जिला चुनाव दफ्तर में लगे फ्लैक्स को हटाया गया, डीसी ने दिए जांच के आदेश

नीरज शर्मा, होशियारपुर

पंजाब के होशियारपुर में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए लगाए गए एक फ्लैक्स पर निर्भया कांड के दुष्कर्मी की तस्वीर लगा दी गई। विवाद गहराने पर जिला चुनाव दफ्तर से इस फ्लैक्स को हटा लिया गया है, लेकिन प्रशासन को बचाव करना मुश्किल हो रहा है। जिला उपायुक्त ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अतिरिक्त जिला उपायुक्त को जांच सौंपी गई है। यह पता नहीं चल पाया कि फ्लैक्स किसने और कब बनवाया, लेकिन यह बात सामने आई है कि इस फ्लैक्स को जिला चुनाव दफ्तर में लगाए जाने से पहले इसी साल 26 जनवरी को होशियारपुर में आयोजित राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जिला चुनाव दफ्तर की झांकी में भी लगाया गया था। उस कार्यक्रम में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर मुख्य अतिथि थे।

शुक्रवार देर रात फ्लैक्स को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। दावा किया गया कि फ्लैक्स पर जिन तीन लोगों की तस्वीर लगाई गई है उनमें से एक फोटो निर्भया दुष्कर्म मामले के दोषी मुकेश की है। ट्विटर पर शेयर की गई इस पोस्ट के स्क्रीन शॉट वाट्सएप पर खूब शेयर किए गए। जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त ने चुनाव आयोग से इसकी जानकारी मांगी है। राजनीतिक गलियारों में भी मामला तूल पकड़ चुका है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सोहन सिंह ठंडल ने जांच की मांग की है।

चुनाव कानूनगो सुखदेव सिंह ने कहा कि यह फ्लैक्स 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में प्रयोग हुआ था, लेकिन इसे किसने बनवाया इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, फ्लैक्स में केवल तस्वीर लगी है, नीचे कोई नाम नहीं है। बिना नाम के कैसे पता किया जा सकता है कि यह कौन है।

पंजाब के होशियारपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग की झांकी पर लगाया गया फ्लैक्स, जिस पर निर्भया के दुष्कर्मी मुकेश (बाएं) की फोटो लगी है। फ्लैक्स की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है।

> यह कह पाना मुश्किल है कि फ्लैक्स में जिस व्यक्ति की तस्वीर छपी है वह दुष्कर्म का दोषी है। कई बार कुछ चेहरे मिलते–जुलते भी होते हैं। फ्लैक्स पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है, जिससे सिद्ध हो सके कि यह फोटो दुष्कर्मी की है। फिर भी इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाएगी।
> **– सुंदर शाम अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री पंजाब**

> एडीसी को जांच के आदेश दिए गए हैं। यह भी पता किया जा रहा है कि यह फ्लैक्स कहां लगा था और अब कहां है। चुनाव हुए दो–तीन महीने गुजर चुके हैं। तस्वीर देखकर ही पता चल पाएगा कि यह किसकी है।
> **– ईशा कालिया, डीसी होशियारपुर**

> कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। जल्दी ही रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।
> **– हरप्रीत सूदन, एडीसी होशियारपुर**

इशरत जहां ने की सुरक्षा न मिलने की शिकायत

जागरण संवाददाता, हावड़ा : तीन तलाक मामले में फरियादी इशरत जहां ने शिकायत की है कि उन्हें पुलिस से कोई संरक्षण नहीं मिला है, जबकि वह अपनी जिंदगी पर खतरे को देखते हुए इसकी मांग कर चुकी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका मकान मालिक उन्हें घर खाली करने को लेकर दबाव बना रहा है।

हावड़ा जिले के गोलाबाड़ी थाने में दर्ज शिकायत में इशरत जहां ने हिजाब में हनुमान चालीसा पाठन से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने पर मकान मालिक और देवर पर अपशब्द का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। इशरत जहां ने बताया, 'मेरे मकान मालिक घर खाली करने को लेकर दबाव बना रहे हैं। मैं कहां जाऊंगी। मुझे अभी तक पुलिस संरक्षण भी नहीं मिला है।'

हालांकि पुलिस ने उनके आरोप को खारिज करते हुए कहा कि एक अधिकारी रोजाना उनका हालचाल जानने के लिए उनके पास जाता है। गोलाबारी थाने के एक अधिकारी ने कहा कि उनके घर के आगे कोई पुलिसकर्मी तो तैनात नहीं किया गया है, लेकिन प्रतिदिन एक अधिकारी उनके घर का दौरा अवश्य करता है। 14 साल की बेटी और आठ साल के बेटे की मां इशरत जहां उन पांच फरियादियों में से हैं, जिन्होंने एक साथ तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक के खिलाफ 22 अगस्त, 2017 को अपना निर्णय सुनाया था। इशरत जहां के पति ने साल 2014 में उन्हें एक साथ तीन तलाक दे दिया था। वह इसके खिलाफ अदालत गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने दी आइपीएस पति की मौत की स्वतंत्र जांच की याचिका वापस लेने की अनुमति

▸ पत्नी ने कहा–केस दर्ज करते वक्त मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी
▸ गौरव दत्त ने सुसाइड नोट में ममता बनर्जी को मौत के लिए ठहराया था जिम्मेदार

नई दिल्ली, एएनआइ : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराने वाले पूर्व आइपीएस अफसर गौरव दत्त की मौत की स्वतंत्र जांच की कोशिशों पर विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 बैच के आइपीएस अफसर की पत्नी श्रेयसी दत्त की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका वापस लेने की उन्हें अनुमति दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने विगत शुक्रवार को कहा कि श्रेयसी दत्त से बातचीत के बाद उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि रिट याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी जाए। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि विगत नौ मई, 2019 को हममें से एक जज (जस्टिस अनिरुद्ध बोस) ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता (श्रेयसी दत्त) से मुलाकात की थी। इससे हमें इस बात पर संतोष है कि उनकी रिट याचिका को वापस लेने दिया जाए। हमारा आदेश भी यही है।

खंडपीठ ने बताया कि विगत नौ मई को वह श्रेयसी से बातचीत करके यह जानना चाहते थे कि वह याचिका क्यों वापस लेना चाहती हैं। इसलिए श्रेयसी को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया था। ध्यान रहे कि श्रेयसी ने अपनी याचिका वापस लेने की अपील की थी। उन्होंने दलील दी थी कि केस दायर करते समय उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसके बाद खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश दिया कि वह श्रेयसी को अब तक की अदालती कार्यवाही में हुए खर्च की भरपाई के लिए 25 हजार रुपये की रकम अदा करे।

क्या था मामला : पश्चिम बंगाल के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अफसर गौरव दत्त को विगत 19 फरवरी को अपने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित घर में कटी हुई कलाई के साथ मृत पाया गया था। दत्त ने पिछले साल ही रिटायरमेंट लिया था। खुदकशी करने वाले गौरव दत्त ने अपने सुसाइड नोट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा था कि मुख्यमंत्री पिछले 10 सालों से उनका शोषण कर रही थीं। दत्त पर एक पुरुष कांस्टेबल का शारीरिक शोषण करने समेत दो मामलों में जांच चल रही थी। 2010 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें सस्पेंड करके कंपलसरी वेटिंग में डाल दिया था।

दिवंगत गौरव की पत्नी श्रेयसी दत्त ने भी तब इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हीं के हाथ का लिखा सुसाइड नोट है। तब उन्होंने मीडिया को बताया था कि सरकार की प्रताड़ना और अपमान से गुजरने के कारण आत्महत्या की है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

आनंदीबेन पटेल उप्र और जगदीप धनकड़ होंगे बंगाल के राज्यपाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चार नए राज्यपालों की नियुक्ति के साथ ही दो राज्यपालों का स्थानांतरण किया है। पिछले साल मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई आनंदीबेन पटेल (77) को उत्तर प्रदेश की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह राम नाईक की जगह लेंगी। आनंदीबेन पटेल की जगह बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।

भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बने बंगाल में केशरीनाथ त्रिपाठी की जगह राजस्थान के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील जगदीप धनकड़ (68) को राज्यपाल बनाया गया है। केशरीनाथ का कार्यकाल अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। जगदीप धनकड़ 1990-91 में केंद्र सरकार में संसदीय कार्य राज्यमंत्री रह चुके हैं। 2003 में धनकड़ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी तरह, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। वह कप्तान सिंह सोलंकी की जगह लेंगे। बिहार में नए राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के मातहत डिप्टी एनएसए के रूप में काम कर रहे एन. रवि को नगालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। खुफिया ब्यूरो (आइबी) के सेवानिवृत्त विशेष निदेशक एन. रवि की नियुक्ति को इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वह एनएससीएन (आइएम) के साथ वार्ताकार की भूमिका निभा रहे थे।

कर्जमाफी के बाद भी किसानों को मिल रहे कुर्की के नोटिस

नईदुनिया, भोपाल

▸ मप्र विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने लगाया आरोप
▸ कृषि मंत्री ने कहा– किसानों को गुमराह कर रही भाजपा

मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया है कि जिन किसानों को सरकार ने कर्जमाफी के प्रमाण पत्र वितरित कर दिए हैं, उन पर कर्ज वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। बैंकों द्वारा संपत्ति कुर्की करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

प्रश्नकाल में विधायक नरोत्तम मिश्रा के प्रश्न पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि 17 जिलों के नोटिस की प्रति उनके पास है। कृषि मंत्री सचिन यादव ने इसके जवाब में कहा कि भाजपा किसानों को गुमराह कर रही है। नोटिस की बात को उन्होंने खारिज कर दिया। इस बीच प्रश्नकाल का समय खत्म हो जाने से चर्चा अधूरी रह गई पर भाजपा विधायक दल ने सही जवाब न देने का आरोप लगाकर सदन से बहिर्गमन किया।

भार्गव ने दतिया के किसान लखन सिंह यादव और अजब सिंह के कुर्की नोटिस को सदन में पढ़कर भी सुनाया और कहा कि किसानों को डराया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ धारा 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्जमाफी की बात अपने वचन पत्र में कही थी, फिर भी किसानों को छला जा रहा है। कर्जमाफी न होने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कमल पटेल के आठ जुलाई के प्रश्न का हवाला देकर कहा कि कर्जमाफी होने के बाद नोटिस मिलने के कारण कांग्रेस राज में 71 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। भार्गव के आरोप पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी कुर्की के ऐसे नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा नोटिस सहकारी बैंक द्वारा जारी किया गया होगा तो वे जिम्मेदार अफसर को निलंबित कर देंगे।

कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए त्रिस्तरीय पैकेज की आवश्यकता

जागरण संवाददाता, जम्मू

कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए करीब छह लाख कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए समुदाय के कुछ सदस्यों ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना के समक्ष रोडमैप पेश करते हुए कहा है कि पंडितों की वापसी के लिए त्रिस्तरीय पैकेज की जरूरत है। इसमें विस्थापितों के शारीरिक और आर्थिक पुनर्वास के साथ उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए, तभी पंडित परिवार अपने घर लौट सकते हैं।

कश्मीरी विस्थापित पंडितों के एक दल ने जम्मू दौरे पर आए अविनाश राय खन्ना को अपना मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि पिछले 30 वर्षों से विस्थापित अपने घरों को नहीं लौट पाए। उन्होंने कहा कि उनकी घर वापसी के लिए जरूरी है कि उनमें विश्वास बहाली के साथ उनके पुनर्वास का एक संपूर्ण कार्यक्रम बनाया जाए। वहीं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आर्थिक पैकेज भी शामिल हो। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में शांति की बहाली के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई भी पुराना दस्तावेज जैसे स्टेट सब्जेक्ट, स्कूल प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, संपत्ति दस्तावेज, जन्म प्रमाणपत्र, वोटर कार्ड, पेंशन कार्ड हो तो उसे विस्थापित होने का प्रमाणपत्र मानकर उसे पैकेज में शामिल किया जाना चाहिए।

कश्मीरी पत्रकारों को जिहादी बताने के विरोध में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, श्रीनगर

कश्मीरी पत्रकारों को जिहादी और आतंकियों का समर्थक बताने के वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्र के विरोध में कश्मीर के पत्रकार संगठनों ने प्रदर्शन किया। शनिवार को पोलव्यू इलाके में स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों ने बैनर उठा रखे थे, जिन पर टेक द लीगल एक्शन अगेनस्ट द रिपोर्टर सलीम पंडित के नारे दर्ज थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दो दिन पहले पंडित ने मनगढ़ंत स्टोरी की है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि यह खबर स्थानीय पत्रकारों को बदनाम करने के लिए है। कश्मीर एडीटर्स गिल्ड, कश्मीर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और अन्य पत्रकार संगठनों ने निंदा करते हुए मामले की छानबीन की मांग की। गौरतलब है कि पंडित ने अपनी खबर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी का हलावा देते हुए दावा किया था कि एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक के संपादक ने पूछताछ में उसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध होने की बात स्वीकार की है।

150 एनकाउंटर करने वाले प्रदीप शर्मा अब करेंगे राजनीति

मुंबई, आइएएनएस : महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर और एनकाउंटर विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा ने त्यागपत्र दे दिया है। शर्मा के भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। एक समय टाइम मैग्जीन के कवर पेज पर स्थान बनाने वाले प्रदीप शर्मा 150 ज्यादा एनकाउंटर में शामिल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और महाराष्ट्र के धुले में पले-बढ़े प्रदीप शर्मा 1983 में महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए थे। प्रदीप शर्मा ने 15 दिन पहले अपना त्यागपत्र डीजीपी को भेजा था, लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। मई 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले प्रदीप शर्मा लंबे समय से खुलेआम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बताते रहे हैं। हालांकि शनिवार को जब मीडिया ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि अभी कुछ तय नहीं किया है। चर्चा है कि भाजपा उन्हें उत्तर-पूर्व मुंबई की अंधेरी या पालघर जिले की नालासोपारा सीट से मैदान में उतार सकती है।

महाराष्ट्र पुलिस में शामिल होने के कुछ दिन बाद उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच टीम का हिस्सा बनाया गया था। यह वह दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। इस टीम को ही मुंबई से अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस टीम ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड के 300 से ज्यादा अपराधियों को मार गिराया। शर्मा ने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार कर जबरन वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया था।

2003 में संदिग्ध आतंकी की हिरासत में मौत पर उन्हें अमरावती ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रदीप को 2008 में एक फर्जी मुठभेड़ मामले में निलंबित किया गया था। उन्होंने निलंबन के खिलाफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। 2016 में उन्हें बरी कर दिया गया।

प्रदीप शर्मा फाइल फोटो

मप्र विधानसभा में उठा शंकराचार्य को पाठ्यक्रम से हटाने का मामला

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश विधानसभा में शून्यकाल के दौरान शंकराचार्य को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम से हटाने का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष सहित अनेक सदस्यों ने इसे बहुसंख्यक हिंदू समाज, देश की संस्कृति और विरासत पर हमला बताया। मामले में आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि ऐसे पाठ्यक्रम चालू रहें, इन्हें रोकना ठीक नहीं।

मामला भाजपा के विश्वास सारंग ने उठाया। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पाठ्यक्रम का कैलेंडर जारी किया है। उसमें बहुत आपत्तिजनक तरीके से शंकराचार्य और पं. दीनदयाल उपाध्याय के पाठ्यक्रम को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शंकराचार्य ने एकता-अखंडता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक देश को एकसूत्र में बांधने का काम किया। देश की संस्कृति-विरासत को संभाला। इसी तरह पं. उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन दिया। इसे पाठ्यक्रम से हटाना हिंदू समाज के विरोध का परिचायक है, आसंदी से इस बारे में निर्देश होना चाहिए।

इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव बोले कि कल एक मंत्रीजी ने सीताजी के अस्तित्व और अशोक वाटिका को लेकर सवाल उठाया था। अब शंकराचार्यजी का नाम हटाना हमारी वैदिक संस्कृति और विरासत से मजाक है। ऐसे मामलों पर चर्चा कराई जाए, हमारी धरोहर-संस्कृति को नष्ट करने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती।

पीसीएस–जे 2018 में आकांक्षा तिवारी ने किया टॉप

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : उप्र न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) यानी पीसीएस-जे परीक्षा 2018 में गोंडा, उप्र की आकांक्षा तिवारी ने टॉप किया है। उप्र लोकसेवा आयोग ने शनिवार शाम परिणाम जारी कर दिया है। तीन चरणों के इम्तिहान के बाद 610 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। परीक्षा में नैनीताल के हरिहर गुप्ता को दूसरा, आजमगढ़ के प्रतीक त्रिपाठी को तीसरा, गाजियाबाद की एकाग्रता सिंह को चौथा व गोंडा के ही गंधर्व पटेल को पांचवां स्थान मिला है। यूपीपीएससी ने साक्षात्कार पूरा होने के तीसरे दिन अब तक के रिकॉर्ड कम समय में बड़ी परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। परिणाम आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in व यूपीपीएससी के सूचना पट पर चस्पा कर दिया गया है। यूपीपीएससी ने पीसीएस-जे 2018 की भर्ती 610 पदों के लिए कराई थी।

आजम खां के खिलाफ तीन और मुकदमे

जागरण संवाददाता, रामपुर

सांसद आजम खां के खिलाफ तीन और मुकदमे दर्ज हुए हैं। अजीमनगर थाने में दर्ज इन मुकदमों में किसानों की जमीनों पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है।

गांव आलियागंज के किसान जाकिर, मुहम्मद आलिम और नूर आलम का आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय सांसद आजम खां, तत्कालीन सीओ सिटी और वर्तमान में यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आले हसन खां और तत्कालीन अजीमनगर थानाध्यक्ष कुशलवीर सिंह द्वारा उनकी भूमि लेने के लिए मारा-पीटा गया। भूमि का बैनामा कराने के लिए जबरन दबाव बनाया गया। उन्हें एक दिन हवालात में भी बंद रखा गया। जमीन न देने पर चोरी, चरस, स्मैक आदि के झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई। इसके बाद भी जब भूमि का बैनामा जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में नहीं किया तो आरोपितों ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया। जमीन को यूनिवर्सिटी के अंदर मिला लिया। अजीमनगर थाना प्रभारी राजीव चौधरी ने बताया कि तीनों किसानों की तहरीर पर सांसद, तत्कालीन सीओ सिटी और तत्कालीन थाना प्रभारी अजीमनगर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

अब तक 27 मुकदमे दर्ज : जिलाधिकारी से आलियागंज गांव के 26 किसानों ने शपथ पत्र देकर जमीन कब्जाने की शिकायत की थी। इसकी जांच कराई गई। जांच के बाद राजस्व कानूनगो मनोज कुमार की ओर से 12 जुलाई को अजीमनगर थाने में सांसद और पूर्व सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इससे पहले एक जून को नदी की जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा हुआ था। अब किसानों की ओर से अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अभी तक जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से संबंधित 27 मुकदमे सांसद पर दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 25 मुकदमे किसानों की ओर से कराए गए हैं।

सपा विधायक दल के सामने हंगामा, आजम के खिलाफ लगे नारे : सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज कराए जा रहे मुकदमों की जांच के लिए शनिवार को रामपुर पहुंचे सपा विधायक दल को विरोध का सामना करना पड़ा। आजम विरोधियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गांधी समाधि पर काफिले को घेर लिया और आजम हाय-हाय के नारे लगे। बाद में 21 सदस्यीय विधायक दल ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर हालात का जायजा लिया।

कमेटी ने हमें नहीं बुलाया : डीएम

जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह का कहना है कि कमेटी ने जिलाधिकारी या एसपी को नहीं बुलाया था। कमेटी में शामिल विधायक जब जाने को थे, तब उससे कुछ देर पहले वहां मौजूद पुलिस वालों से पूछा कि क्या जिलाधिकारी और एसपी मिलेंगे। इस पर पुलिस वालों ने हमें मैसेज किया, लेकिन इसके चंद मिनट बाद ही कमेटी यहां से चली गई। इस कारण मिल ही नहीं सके।

अगले माह चीन जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले माह चीन का दौरा करेंगे। वह वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का आधार तैयार करेंगे। मोदी अक्टूबर में चीन की यात्रा पर जाएंगे जहां वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर बीजिंग के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वह वरिष्ठ चीनी नेतृत्व के अलावा अपने समकक्ष चीनी विदेश मंत्री वांग यी से वैश्विक मुद्दों के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य मोदी और चिनफिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक का आधार तैयार करना है। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। दोनों नेता परस्पर संवाद बढ़ाने, व्यापार सहयोग एवं निवेश को गति देने समेत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर बल देंगे। बता दें कि डोकलाम विवाद के बाद गत वर्ष अप्रैल माह में चीनी शहर वुहान में दोनों नेताओं के बीच पहली अनौपचारिक बैठक हुई थी।

तैयारी

> कोलकाता में आयोजित होगी रैली, राज्यभर से जुटे पार्टी कार्यकर्ता, ममता ने दिया है 'गणतंत्र लौटाओ, मशीन नहीं, बैलेट लौटाओ' का नारा

आज शहीद दिवस रैली से ममता खोलेंगी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस की रविवार को कोलकाता में आयोजित होने वाली शहीद दिवस रैली से मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। दरअसल, ममता ने इस बार रैली का नारा ही दिया है- 'गणतंत्र लौटाओ, मशीन नहीं, बैलेट लौटाओ'। रैली के दौरान रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम मौजूद रहेगी। ममता बनर्जी के संबोधन में भी प्रशांत किशोर की रणनीति दिखाई पड़ सकती है।

सभा के मंच से दीदी क्या संदेश देंगी, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार से मायूस पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना मुख्य लक्ष्य है। माना जा रहा है कि दीदी इस सभा से ही 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की रूपरेखा तैयार करेंगी। साथ ही ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। वह यह बताने की कोशिश करेंगी कि बंगाल में भाजपा ईवीएम की वजह से जीती है।

रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम की रहेगी नजर : चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर व उनकी पूरी टीम रैली में मौजूद रहेगी और लोगों का मूड भांपेगी। गौरतलब है कि भाजपा की नजर बंगाल पर है और यहां माकपा व कांग्रेस को पीछे छोड़कर भाजपा दूसरे नंबर पर आ गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की नजर बंगाल पर है।

पिछले दो वर्षों से ममता राष्ट्रीय राजनीति में जमीन तलाश रही थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में ममता मंच से पार्टी के लिए नया दिशानिर्देश व संकल्प निर्धारित कर सकती हैं। दो साल पहले ममता ने 21 जुलाई को मंच से 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' का नारा दिया था। पिछले साल उनका नारा था '2019, भाजपा फिनिश' संभव है कि रविवार को फिर ममता एक नया नारा बुलंद करेंगी।

अन्य दलों के नेता हो सकते हैं शामिल : लगभग हर साल इस सभा के मंच पर अन्य दलों के नेता तृणमूल का दामन थामते हैं। इस साल क्या होता है, इस पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ माह में तृणमूल छोड़कर कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं।

दो दिन पहले ही पहुंचे समर्थक : इस बार दो दिन पहले से ही राज्य के विभिन्न जिलों से पार्टी कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचने लगे। इस बार भी भारी भीड़ जुटने का दावा किया गया है।

चरमरा सकती है महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था : सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक कोलकाता में माल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई है। हेस्टिंग क्रासिंग, कैथेड्राल रोड, हास्पिटल रोड आदि सड़कों पर नो पार्किंग रहेगी। ट्राम सेवा सभा के समय बंद रहेगी। साथ ही सभास्थल के आसपास की सड़कों मसलन लेनिन सरणी, सेंट्रल एवेन्यू और एसएन बनर्जी रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध : रैली को देखते हुए सुरक्षा के लिए पांच हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 18 स्थानों पर एंबुलेंस, विभिन्न जगहों पर 10 ड्राप गेट, आठ जगहों पर बड़े स्क्रीन, 10 मेट्रो स्टेशनों के अलावा हावड़ा व सियालदह स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे।

ममता बनर्जी फाइल फोटो

तृणमूल कांग्रेस क्यों मनाती है शहीद दिवस

21 जुलाई, 1993 को युवा कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व में राइटर्स अभियान हुआ था। पुलिस के रोकने के बावजूद वह समर्थकों के साथ आगे बढ़ रही थी। तत्कालीन ज्योति बसु की सरकार के निर्देश पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। इस दिन को ममता हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाती हैं।

कर्नाटक में शक्ति परीक्षण से पहले रणनीति बनाने में जुटे राजनीतिक दल

▸ येद्दयुरप्पा बोले– बहुमत है तो साबित कीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 माह पुरानी जदएस-कांग्रेस सरकार के सोमवार को होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले राजनीतिक पार्टियां गुपचुप तरीके से रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को दो बार दी गई समयसीमा की अनदेखी करके शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दयुरप्पा ने शनिवार को अपने पार्टी विधायकों से मुलाकात की और उनके साथ सोमवार को विधानसभा में अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार-विमर्श किया। येद्दयुरप्पा ने कहा, 'हमारी मांग है कि अगर आपके पास बहुमत है तो साबित कीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए और जाइए। इस्तीफा न देकर वे समय बर्बाद कर रहे हैं। शायद उन्हें भ्रम है कि सोमवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी।' उनका इशारा कुमारस्वामी और कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की ओर था।

इस बीच, मुंबई में ठहरे कांग्रेस-जदएस के बागी विधायक इस्तीफों को लेकर अपने रुख पर कायम हैं। वहीं, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और मंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को आगे की रणनीति पर मंत्रणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और इस्तीफा वापस लेने वाले कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने भी ताजा राजनीतिक हालात पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने भी रविवार शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने साफ किया है कि विश्वास प्रस्ताव पर सोमवार को ही मतदान कराया जाएगा।

इस बीच, चर्चा है कि ज्योतिषियों ने कुमारस्वामी को विश्वास प्रस्ताव पर सोमवार के बजाय मंगलवार को मतदान कराने की सलाह दी है, लेकिन जदएस प्रवक्ता रमेश बाबू ने इससे इन्कार किया है।